Millennium Post- 26- April-2022

'4 lakh hectare under natural farming now'

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: Agriculture Minister Narendra Singh Tomar on Monday said about 4 lakh hectare has been brought under natural farming so far as part of a sub-scheme of the Paramparagat Krishi Vikas Yojana and think-tank Niti Aayog will prepare a roadmap to scale this up.

Tomar, while addressing a national workshop on innovative agriculture here, said the need of the hour is to do farming that works in harmony with nature, reduces the cost of production, ensures good-quality produce and profits to farmers.

Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, parts of Haryana and Gujarat are gradually adapting to natural farming. More farmers will join after seeing the success stories, he said.

Tomar said Niti Aayog will prepare a roadmap on natural farming after deliberation with farmers, scientists and agri-varsities' vice chancellors in today's workshop and the ministry will move forward accordingly.

Agriculture Minister Narendra Singh Tomar said some may have "apprehension that production might decline by shifting to natural farming. Such people after seeing the success stories of natural farming will be able to adapt easily."

Natural farming should be promoted where no chemicals are used in farming, he added.

According to the minister, about 38 lakh hectares have been brought under organic farming at present. About 4 lakh hectares of area is under natural farming so far as part of a sub-scheme of the Paramparagat Krishi Vikas Yojana.

A central programme is underway to certify farm fields where no chemicals are used in areas of Nicobar and Ladakh. The centre is pursuing with states to identify such farm fields for certification, Narendra Singh Tomar said.

The Statesman- 26- April-2022

NGT raps DJB over failure of 'stringent action' against sewage dumping

AGENCIES
NEW DELHI, 25 APRIL

The National Green Tribunal has come down heavily over the Delhi Jal Board over a plea against the dumping of sewage carried by vehicles on roads and drains in various locations in south Delhi, particularly at Chandan Hola Main Road Bus Stand near Pulliya, Gadaipur Bandh Road, DLF, and Vasant Kunj Farm House.

The green court observed that even the Delhi Pollution Control Committee has acknowledged that the situation is disturbing, continuous, sustained, and stringent action is required by the statutory authorities, particularly DJB which has given licences that are being misused in violation of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

The violations are also offences under Sections 268 to 270 of the IPC.

"There appears to be serious failure to monitor compliance of Delhi Water Board Septage Management Regulation, 2018 by the DJB. There is a need to review the current mechanisms and evolve a more effective system to prevent such incidents. Violators need to be identified and proceeded against in the interest of rule of law, public health, and the environment. Licensed service providers must transport septage to the Sewage Pumping Stations (SPS) and pre-notified STPs having facilities to treat the septage and duly record the same with the proper manifest system. If septage is disposed of illegally, there must be a mechanism to report and take action," said the tribunal in the order passed on April 22.

The tribunal constituted a joint committee headed by Delhi High Court's former judge, Justice S.P. Garg, with nominees of the CPCB, the DPCC, and Chief Engineer, DJB. The Committee may meet within two weeks to take stock of the situation in the light of the above observations. It may undertake visits to such sites as may be found appropriate and devise appropriate monitoring mechanisms to prevent such incidents. It may coordinate with the stakeholders and any other department or institution. It may give its report within three months, said the NGT.

The order also said that the honorarium payable to Justice Garg will be paid by the DJB, in case it is not already being paid in connection with any other work entrusted by the NGT.

The Economic Times- 26- April-2022

140 Reservoirs' Storage 30% More than 10-year Average

NEW DELHI Total water storage in 140 reservoirs in the country whose live storage status is monitored by the Central Water Commission is at present almost 30% higher than the average for the same period for the last 10 years. These reservoirs had 68.739 billion cubic meter (bcm) as of week ended April 22, which is 15.235 bcm more than the 10-year average, latest data from the commission shows. This equals to 39% of the storage capacity at full reservoirs level . The 113 reservoirs used for irrigation purposes are at 43% of their capacity, the water commission said. A year ago, storage in the 140 reservoirs was at 63.344 bcm. **–PTI**

The Pioneer- 26- April-2022

बाढ़ नियंत्रण से जुड़े सभी काम हर हाल में 15 जून तक पूरा करें: सीएम

● बाढ़ परियोजनाओं की समीक्षा बैठक

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाढ़ नियंत्रण से सम्बंधित सभी काम प्रत्येक दशा तक 15 जून तक पूरा कर लिया जाए। बाढ़ बचाव कार्य में विभाग के अधिकारी फील्ड में उतरें और मौके पर जाएं। एक सप्ताह के भीतर कार्यस्थलों की ड्रोन वीडियो फोटो उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नदियों की ड्रेजिंग से निकली उपखनिज बालू,सिल्ट की नीलामी में पारदर्शिता बरती जाए। हर हाल में यह बालू सिल्ट 15 जून तक वहां से हट जाए। बालू नीलामी के कार्य का भौतिक सत्यापन भी कराया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि तटबंधों की मरम्मत के कार्य को शीर्ष प्राथमिकता दी जाए। अति संवेदनशील, संवेदनशील स्थलों पर रिजर्व स्टॉक का प्रबंध कर लिया जाए। नदी की धारा की चपेट में आने वाले अति संवेदनशील संवेदनशील स्थलों को चिन्हित कर मरम्मत सुरक्षात्मक कार्य हर हाल में 31 मई तक पूरा करा लिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं में ठेके टेंडर के लिए फर्म एजेंसी के चयन करते समय पूरी पारदर्शिता बरतें।

Haribhoomi- 26- April-2022

नर्मदा पुनर्जीवन के लिए कार्यों की समीक्षा करने अमरकंटक पहुंचे मुख्यमंत्री

जिस प्रकार देश में गंगा जी का नाम उसी तरह मप्र में नर्मदा जी का नाम

हरिभूमि न्यूज ⏭ भोपाल

अमरकंटक में नर्मदा पुनर्जीवन कार्यक्रम के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिस प्रकार देश में गंगा जी का नाम है, उसी तरह मप्र में नर्मदा जी का नाम है। अमरकंटक कोई साधारण जगह नहीं है। यह ऋषि-मुनियों तथा तपस्वियों की भूमि है। नर्मदा नदी के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए नर्मदा सेवा यात्रा शुरू की जाएगी। पूर्व की नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान जो योजना बनाई गई थी, उसमें फलों की खेती, वृक्षा-रोपण का बृहद स्तर पर अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान में 16 विभागों के साथ समाज की अहम भूमिका रही है।

मुख्यमंत्री रविवार को अमरकंटक पहुंचें थे। वे सुबह 10 बजे जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट से हेलीकाप्टर से अमरकंटक पहुंचे थे। उनके समक्ष नर्मदा नदी के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए तैयार रोडमैप का प्रजेंटेशन किया गया। वे एक मई को नर्मदा सेवा अभियान से जुड़े लोग जन-जागरण अभियान का शुभारंभ करेंगे, जबकि पर्यावरण दिवस 5 जून के दिन विभिन्न स्थान पर अलग-अलग प्रजाति के पौधे लगाने का संकल्प लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा-अमरकंटक कोई साधारण जगह नहीं है, यह ऋषि-मुनियों तथा तपस्वियों की भूमि

संरक्षण-संवर्धन के लिए पौध-रोपण और जल-संरचनाएं जरूरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव में अमृत सरोवर बनाने का आह्वान किया है। नर्मदा नदी के संरक्षण-संवर्धन के लिए पौध-रोपण और जल-संरचनाएं बनाना आवश्यक है। अमृत सरोवर के रूप में बनने वाली जल-संरचनाएं नर्मदा तट पर स्थित हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि नर्मदा जी की 41 सहायक नदियों के तट पर भी अमृत सरोवर का निर्माण किया जाएगा, जिससे नर्मदा नदी का प्रवाह और अधिक विस्तृत एवं विशाल हो सके। साथ ही हर जगह से पानी नर्मदा नदी में आता रहे।

नर्मदा के संरक्षण और संवर्धन से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का होगा विकास : मंत्री यादव

केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि नर्मदा नदी के संरक्षण और संवर्धन के लिए नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक में बैठक कर विचार-विमर्श किया गया है। नर्मदा नदी मप्र के साथ अन्य राज्यों की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक जीवन की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि नर्मदा के संरक्षण और संवर्धन से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का विकास होगा। उन्होंने कहा कि नर्मदा नदी देश की महत्वपूर्ण नदी है, जिसे बचाने के लिए बेहतर कार्य-योजना की जरूरत है। मुझे इस बात की खुशी है कि 2018 में जो नर्मदा सेवा क्षेत्र का विकास कार्य शुरू किया गया था, उसे और आगे बढ़ाने के लिए विस्तृत चर्चा की जा रही है।

केंद्रीय मंत्री पटेल, प्रदेश वन मंत्री ने दिए सुझाव

केन्द्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, मप्र के वन मंत्री विजय शाह, पर्यावरण विद् सुरेश सोनी ने भी नर्मदा के संरक्षण और संवर्धन के लिए सुझाव दिए। प्रमुख सचिव वन अशोक वर्णवाल ने इस आयोजन की रूपरेखा पर प्रकाश डाला। कलेक्टर अनूपपुर सोनिया मीना ने जल-संरक्षण एवं सौन्दर्यीकरण के लिए कराए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। इस मौके पर संभागायुक्त शहडोल संभाग राजीव शर्मा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डीसी सागर, मुख्य वन संरक्षक पीके वर्मा एवं केन्द्र सरकार के अधिकारी उपस्थित थे।

Rashtriya Sahara- 26- April-2022

गंगा जल आपूर्ति योजना जल्द पूरी करें : नीतीश

■ पटना (एसएनबी)।

■ मुख्यमंत्री ने की बाढ़ पूर्व की तैयारियों और गंगा जल आपूर्ति योजना की समीक्षा

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा जल आपूर्ति योजना को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। 1 अणे मार्ग स्थित संकल्प में सोमवार को मुख्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की और कई जरूरी दिशा-निर्देश दिये। वैठक में खासकर वाढ़ पूर्व की तैयारियों एवं गंगा जल आपूर्ति योजना की विस्तृत समीक्षा की गई।

समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को गंगा जल का स्टोरेज करने के साथ-साथ इसके शुद्धिकरण और सप्लाई कार्य प्रगति की निरंतर निगरानी करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पदाधिकारी और अभियंता इस काम को जमीनी स्तर पर देखें और पाइप लाइन की सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था रखें। सीएम ने जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग को आपस में समन्वय स्थापित कर तेजी से कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि गंगा जल आपूर्ति योजना के क्रियान्वयन में आम लोगों का काफी सहयोग मिला है। राजगीर, गया, वोधगया व नवादा में गंगा नदी के जल को शुद्ध कर पेयजल के रूप में जल्द से जल्द सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्य करें। इससे लोगों को सुविधा होगी और भू-जल स्तर भी मेंटेन रहेगा। मुख्यमंत्री ने वाढ़ पूर्व सुरक्षात्मक कार्यों को ससमय पूरा करने का निर्देश देते हुए कहा कि वाढ़ अवधि में कराये जाने वाले कार्यों की पूरी तैयारी रखें। उन्होंने कहा कि सात निश्चय-2 के अंतर्गत हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए योजनावद्ध ढंग से कार्य करें। छोटी-छोटी नदियों को जोड़ने की योजना भी वनायें और इसको लेकर व्यावहारिक आकलन करायें। उन्होंने कहा कि छोटी नदियों के आपस में जुड़ने से जल संरक्षित रहेगा और इससे लोगों को सिंचाई कार्य में भी सुविधा होगी।

Financial Express- 26-April-2022

HEATWAVES SINCE LATE MARCH

Wheat crop hit in Punjab, Haryana

Output to be at least 10% below estimate

SANDIP DAS
Karnal (Haryana) & Rajpura, Khanna (Punjab), April 25

RAVINDER KUMAR, A wheat farmer from Sidpur village of Karnal district, Haryana, says his crop yield has dropped to 17-18 quintal per acre in the current season compared with 24-25 quintal last year. Heatwaves in the second half of March with temperatures rising to 40 degrees Celsius hit the crop at the ripening stage, he says. "The bulk of the grains are shrivelled or shrunken," Kumar said, adding that his income from this year's wheat crop would be just ₹34,000 per acre, while he could have got ₹48,000 per acre if the yield was good.

Farmers like Kumar could have an average net income of just around ₹15,000 per acre this year, after taking into consideration costs of seed, inputs like fertilisers and pesticides, labour and other costs.

Just around 200 km away in Rajpura mandi, one of the biggest in Punjab, Gurcharan Singh, a farmer at Bal Suan village, part of Patiala district, who had sown wheat in 11 acres, says his per acre yield has dropped to around 17 quintal this year, from 21 quintal he got in 2021.

Scientists say that day temperatures should ideally be in the early 30 degrees Celsius when the kernel accumulates starch and nutrients.

"There would be a 10-15% drop in yield of wheat crops, especially in Punjab and Haryana because of excessive heat during March," said Ajay Vir Jhakar, chairman, Bharat Krishak Samaj.

According to a Rajpura mandi official, extreme heat in March and early April has increased the share of shrivelled grain in the crop from the usual level of around 5% to 10-20% in the state. Farmers are bringing in shrivelled grains beyond the Food Corporation of India (FCI) prescribed maximum permissible limit of 6%.

The government is considering a proposal to relax norms for shrivelled grain soon. It is yet to officially ascertain the extent of yield losses in the case of wheat while in the second advance estimates of food grain production released in February, the government had estimated wheat production of 111 million tonne (MT) in 2021-22, compared with 109 MT in the previous year. At the National Kharif Conference held last week, agriculture minister Narendra Singh Tomar, however, ruled out any drop in wheat production this year. But going by the feed-backs from key mandis, the production could be at least 10% lower than the estimate.

In Uttar Pradesh, the biggest producer of wheat in the country, sowing was carried out on 9.77 million hectare (MH) this year, marginally less than last year. The production is unlikely to be disrupted this year as farmers provided adequate irrigation to the crop during the rising temperature in March.

Madhya Pradesh government officials said that wheat production is unlikely to be impacted because of the heatwave, but because of the state government's thrust on exports, government procurement has been sluggish.

Punjab, Haryana, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh contributed 76% to the country's wheat production in 2019-20.

In terms of wheat production, Punjab and Haryana had a share of 16% and 11%, respectively, in the country's production of 107 MT of grain in the 2019-20 crop year (July-June). The two states had a share of 32% & 19% respectively in the wheat marketing year 2020-21.

Farmers at the Rajpura mandi in Punjab

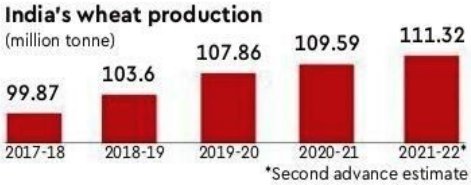

ON THE WHEAT TRAIL-II

A two-part series looks at India's wheat trade amid the prospect of an unprecedented export boom

Rajasthan Patrika- 26- April-2022

आजादी के अमृत महोत्सव के तहत लिए गए संकल्प में 75 अमृत सरोवर तैयार करने की योजना

देश का पहला अमृत सरोवर रामपुर में बनकर हुआ तैयार

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रामपुर. योगी सरकार के प्रयासों से रामपुर की ग्राम पंचायत पटवाई में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार चुका है। राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना को साकार करने में जुटी हैं।

आजादी के अमृत महोत्सव के तहत लिए गये संकल्पों में से 75 अमृत सरोवर की योजना के कार्य युद्ध स्तर पर करा रही है। इन प्रयासों की कड़ी में सबसे पहले रामपुर में गंदगी से पटे तालाब को कुछ ही

हफ्तों में साफ करके उसका कायाकल्प किया गया है। यहां से कब्जे हटाए गए। अब यह तालाब रमणीक स्थल के रूप में ग्रामीण पर्यटन का बड़ा केन्द्र बन चुका है।

योगी सरकार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ भारत, जलशक्ति तथा कब्जा मुक्ति के आह्वान पर अमृत सरोवर बनाने के काम को रामपुर से शुरू किया है। रामपुर में 75 तालाबों का चयन अमृत सरोवर के रूप में विकसित करने के लिए किया गया। चयनित तालाबों में से विकास विकासखंड शाहबाद के ग्राम पंचायत पटवाई के तालाब का कार्य पूरा कराया गया। अब ग्राम पंचायत सिंगन खेड़ा में सबसे अधिक क्षेत्रफल (1.67 हेक्टेयर) वाले तालाब का काम भी शुरू हो चुका है। अगले 03 महीनों में कूड़े और गंदगी से पटे रहने वाला यह तालाब अमृत सरोवर के रूप में ग्रामीण पर्यटन का बढ़ा केन्द्र बन जाएगा।

मन की बात में पीएम मोदी ने की तारीफ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को मन की बात में यूपी के रामपुर में यूपी सरकार की ओर से तैयार किये गये इस पहले अमृत सरोवर की तारीफ और तालाब की सफाई में जुटने वाले गांव के लोगों को बधाई भी दी। पीएम मोदी ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब आपके अपने शहर में 75 अमृत सरोवर होंगे। उन्होंने कहा कि आजादी के 75वें साल में आजादी के अमृत महोत्सव में देश जिन संकल्पों को लेकर आगे बढ़ रहा है उनमें जल संरक्षण भी एक है। अमृत महोत्सव के दौरान हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे।

नौका विहार के साथ हरियाली का आनन्द लेने का भी मौका

ग्राम पंचायत पटवाई में बने भारत के पहले अमृत सरोवर का काम राज्य सरकार ने इस साल जनवरी माह से शुरू किया था। मनरेगा कन्वर्जेन्स, क्षेत्र पंचायत निधि और ग्राम पंचायत निधि से सरोवर की रिटेनिंग वॉल, चारदिवारी, इंटरलॉकिंग, फूड कोर्ट, स्टोन पिचिंग, पैडल वोट, ग्रीन एरिया, फव्वारे लगाए गये। यहां प्रकाश की भी व्यवस्था की गई। इस सरोवर के बन जाने से रामपुर के गांवों का भूजल स्तर भी सुधरेगा। साथ ही लोगों को नौका विहार के साथ यहां की हरियाली का आनन्द लेने का मौका मिलेगा। सरोवर के विकास से ग्राम वासियों की आय के साधन सृजित होंगे और ग्राम पंचायत की आय में भी वृद्धि होगी।